

दि कर्मिक पोस्ट

Email- thekaarmiicpost@gmail.com

Global
School Of
Excellence,
Obedullaganj

वर्ष : 12, अंक : 37

(प्रति बुधवार),

इन्दौर, 9 सितंबर 2026 से 15 सितंबर 2026

पेज : 8

कीमत : 3 रुपये

स्वच्छ वायु दिवस पर राहत की तस्वीर, 108 शहरों में प्रदूषण घटने का दावा, कई शहरों में हवा अब भी जहरीली



नई दिल्ली। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, भारत के 108 शहरों में हवा हुई बेहतर, लेकिन कई शहर अब भी मानकों से बाहर; स्वच्छ वायु दिवस पर प्रदूषण घटाने की चुनौती और तेज कार्रवाई की जरूरत सामने आई सुधार के बावजूद केवल 14 एनसीएपी शहर 2025-26 में सालाना पीएम10 के राष्ट्रीय मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर खरे उतरे।

एनसीएपी के 130 शहरों में 108 शहरों ने 2025-26 में 2017-18 के मुकाबले पीएम10 प्रदूषण में कमी दर्ज की। 72 शहरों में पीएम10 प्रदूषण 20 प्रतिशत से अधिक घटा, जबकि 26 शहरों में कमी 40 प्रतिशत से ज्यादा रही। सुधार के बावजूद केवल 14 एनसीएपी शहर 2025-26 में सालाना पीएम10 के राष्ट्रीय मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर खरे उतरे। विशाखापत्तनम में पीएम10 स्तर 76 से बढ़कर 119 माइक्रोग्राम हुआ, जिससे शहरों के बीच प्रदूषण की असमान स्थिति सामने आई। दिल्ली में पीएम10 200 और पीएम2.5 102 माइक्रोग्राम रहा, जो बताता है कि सुधार के बावजूद प्रदूषण गंभीर चुनौती बना हुआ। हर साल सात सितंबर को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस या नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का

अंतराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता रहा है। भारत में इसे स्वच्छ वायु दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को वायु प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूक करना और साफ हवा के लिए जरूरी कदमों पर ध्यान दिलाना है। भारत के लिए यह दिन खास महत्व रखता है। देश के कई बड़े शहर आज भी प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। वाहनों का धुआं, उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण, निर्माण कार्यों की धूल, कचरा जलाना और पराली जैसे कारण हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इसका असर केवल पर्यावरण पर नहीं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी एनसीएपी के तहत शामिल 130 शहरों में से 108 शहरों में वर्ष 2025-26 के दौरान पीएम10 का सालाना स्तर 2017-18 की तुलना में कम हुआ है। इनमें 72 शहर ऐसे हैं जहां पीएम10 में 20 प्रतिशत से अधिक कमी दर्ज की गई। वहीं 26 शहरों में कमी 40 प्रतिशत से अधिक रही। यह आंकड़ा बताता है कि देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण कम करने के प्रयासों का असर दिखाई दे रहा है। लेकिन तस्वीर पूरी तरह अच्छी नहीं है। 130 में से 22 शहरों में पीएम10 का स्तर 2017-18 की तुलना में बढ़ गया। इसका मतलब है कि देश के सभी शहरों में प्रदूषण कम होने की एक जैसी स्थिति नहीं है। सरकारी आंकड़ों को समझते समय एक महत्वपूर्ण बात ध्यान

रखना जरूरी है। किसी शहर में प्रदूषण पहले के मुकाबले कम होना यह साबित नहीं करता कि वहां की हवा अब साफ है।

भारत में सालाना पीएम10 के लिए राष्ट्रीय मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। वर्ष 2025-26 में एनसीएपी के 130 शहरों में से केवल 14 शहर इस मानक को पूरा कर पाए। वर्ष 2017-18 में ऐसे शहरों की संख्या केवल छह थी। इसलिए किसी शहर की स्थिति समझने के लिए दो बातें देखनी चाहिए। पहली, क्या प्रदूषण पहले के मुकाबले कम हुआ है? दूसरी, क्या वर्तमान प्रदूषण राष्ट्रीय मानक के भीतर है?

उदाहरण के लिए, कोहिमा में 2025-26 में पीएम10 का स्तर 47 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जो राष्ट्रीय मानक से कम है। दूसरी ओर, दिल्ली में यह स्तर 200 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। दिल्ली में पहले की तुलना में सुधार हुआ है, लेकिन प्रदूषण अभी भी राष्ट्रीय सीमा से काफी ऊपर है। जहां ज्यादातर शहरों में पीएम10 का स्तर घटा, वहीं कुछ शहरों में प्रदूषण बढ़ा भी है। इनमें विशाखापत्तनम का आंकड़ा खास चिंता पैदा करता है। विशाखापत्तनम में 2017-18 में पीएम10 का सालाना स्तर 76 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर 119 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। यानी इसमें 56 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई।

यह दिखाता है कि स्वच्छ हवा की लड़ाई में हर शहर की अपनी चुनौतियां हैं। केवल योजनाएं बनाने या धन खर्च करने से समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर प्रदूषण के कारणों को पहचानना और उन पर लगातार कार्रवाई करना जरूरी है। पीएम2.5 के आंकड़े भी देश के प्रमुख शहरों की अलग तस्वीर दिखाते हैं। साल 2025-26 में हैदराबाद में पीएम2.5 का सालाना स्तर 34 माइक्रोग्राम, सूरत में 32 माइक्रोग्राम और मुंबई में 33 माइक्रोग्राम रहा। भारत में पीएम2.5 का सालाना राष्ट्रीय मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। इस लिहाज से इन तीनों शहरों का स्तर मानक के भीतर रहा। पुणे में यह 41 माइक्रोग्राम रहा, जो मानक से थोड़ा अधिक है। दिल्ली में पीएम2.5 का स्तर 102 माइक्रोग्राम रहा, जो काफी अधिक है। वायु प्रदूषण की चर्चा में पीएम10, पीएम2.5 और एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्वआई को अलग-अलग समझना जरूरी है।

एक्वआई किसी समय हवा की स्थिति बताने में मदद करता है। इसमें शून्य से 50 तक की हवा को अच्छी, 51 से 100 तक संतोषजनक और 101 से 200 तक मध्यम माना जाता है। 201 से 300 तक हवा खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब और 401 से 500 तक गंभीर मानी जाती है। वहीं, पीएम10 और पीएम2.5 के सालाना आंकड़े लंबे समय की स्थिति को समझने में मदद करते हैं। इसलिए किसी शहर का एक दिन का एक्वआई और उसका सालाना पीएम10 स्तर एक ही चीज नहीं है।

जलवायु संकट का नया चेहरा- बढ़ती गर्मी और जंगल की आग से जहरीली हो रही हवा- डब्ल्यूएमओ

मुंबई। जलवायु संकट अब सिर्फ बढ़ते तापमान और बदलते मौसम तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी सांसों में भी घुल रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की नई रिपोर्ट ने वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के बीच बढ़ते खतरनाक संबंध को उजागर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 1990 के दशक के बाद से दुनिया में भारी धुएं वाली जंगल की आग की घटनाएं करीब तीन गुना बढ़ गई हैं, जिनसे 2010-2018 के दौरान हर साल करीब 1 लाख अतिरिक्त मौतों का अनुमान है। जंगलों की आग से हर साल करीब 14.3 करोड़ टन जहरीले कार्बनिक प्रदूषक हवा में पहुंच रहे हैं, जबकि पारंपरिक मॉडल इनके स्वास्थ्य प्रभावों और मौतों को 93 फीसदी तक कम आंक सकते हैं। बढ़ती गर्मी और लू जमीन के पास ओजोन प्रदूषण को भी बढ़ा रही है, जिससे समय से पहले मौतों का खतरा और गहरा सकता है। भारत के लिए चिंता और बढ़ी है, क्योंकि 2025 में यहां पीएम2.5 का स्तर लंबे समय के औसत से ऊपर रहा। साफ हवा में सांस लेना हर इंसान का अधिकार है, लेकिन बदलती जलवायु इस अधिकार को लगातार चुनौती दे रही है। जंगलों में भड़कती आग, बढ़ती गर्मी और लंबे समय तक चलने वाली लू न केवल तापमान को बढ़ा रही हैं, बल्कि हवा में घुलने वाले जहरीले

प्रदूषकों के बोझ को भी बढ़ा रही हैं। इससे वायु गुणवत्ता में सुधार लाने और मानव स्वास्थ्य व पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने की वैश्विक कोशिशों पर असर पड़ सकता है। 7 सितंबर को 'इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज' के अवसर पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने अपनी नई रिपोर्ट में वायु गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन के बीच गहरे संबंध को उजागर किया है। रिपोर्ट ने चेताया है कि जलवायु परिवर्तन और जहरीली हवा अब दो अलग-अलग संकट नहीं रहे, बल्कि एक-दूसरे को और विकराल बनाने वाले खतरनाक चक्र में बदल चुके हैं। बढ़ती गर्मी प्रदूषण को हवा में और जहरीला बना रही है, जबकि प्रदूषण जलवायु संकट को और गहरा कर रहा है। इस दुष्चक्र की सबसे भारी कीमत इंसानी सेहत, जंगलों, खेती और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को चुकानी पड़ रही है। रिपोर्ट में डब्ल्यूएमओ के ग्लोबल एटमॉस्फियर वॉच नेटवर्क से मिले आंकड़ों और दुनिया भर के वैज्ञानिकों के शोध को शामिल किया है। संदेश बेहद स्पष्ट है कि वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को अलग-अलग समस्याओं की तरह नहीं देखा जा सकता। दोनों एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश के विकास और लोकतंत्र को सशक्त करने में अविस्मरणीय योगदान दिया



भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष केवल सत्ता के नहीं बल्कि निरंतर सेवा और राष्ट्र निर्माण के 25 वर्ष हैं। सात अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई यह संवैधानिक यात्रा आज एक ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंची है। गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री तक उन्होंने जन सेवा को अपना ध्येय माना और आज भी संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश के विकास और लोकतंत्र को सशक्त करने में अविस्मरणीय योगदान दिया है। इस गौरवपूर्ण यात्रा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, एक माह तक सेवा-संकल्प अभियान चलाया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता सेवा का संस्कार है। यही संस्कार आज %सेवा-संकल्प अभियान% के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के 25 वर्ष के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों को हम जनता के बीच ले जाएंगे। इस अभियान से जनकल्याण के लिए संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। अभियान को जन सहभागिता से जन संवाद का माध्यम बनाया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सेवा-संकल्प अभियान के संबंध में मंत्रालय में आयोजित बैठक में निर्देश दिए। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा गौर, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, राज्यसभा सांसद डॉ. कविता पाटीदार, मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में जारी जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत संचालित गतिविधियों को सेवा-संकल्प अभियान में सम्मिलित करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। सेवा-संकल्प अभियान की अवधि में आने वाले प्रत्येक शुक्रवार को सभी जिलों में जनकल्याण और जन संवाद की विशेष गतिविधियां संचालित की जाएं। अभियान के अंतर्गत प्रदेश के नवाचारों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित और प्रोत्साहित किया जाए। अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में संकलित विकास पुस्तिकाएं जन-जन तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी मंत्री अपने-अपने विभाग और प्रभार के जिलों

में इस अभियान की नियमित समीक्षा करें। हर जिले में तिथिवार कार्य योजना तय की जाए। जिन कार्यक्रमों में लाभार्थी संपर्क में है, वहां शासन द्वारा योजनावार लाभार्थी सूची संबंधित को उपलब्ध कराई जाए। जिला स्तर पर विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए। मध्यप्रदेश इस अभियान में ऐसा मॉडल प्रस्तुत करे, जिसे देश में सुशासन, सेवा और जन सहभागिता के उदाहरण के रूप में देखा जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर को उज्जैन स्थित महाकाल महालोक में बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रदेश में जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं और कार्यों का लोकार्पण या भूमि-पूजन किया है अथवा अन्य कोई महत्वपूर्ण सौगात दी है, उन सभी स्थानों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य की प्रस्तुति अहमदाबाद अथवा वडनगर में की जाए। प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर नर्मदा परियोजना और सरदार सरोवर बांध से जिन जिलों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है, उन जिलों में नर्मदा परियोजना पर केन्द्रित गतिविधियां संचालित की जाएं। इसी प्रकार केन-बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में प्रधानमंत्री श्री मोदी की इस पहल से जन-जन को अवगत कराया जाए।

प्रदेश में विकसित प्रमुख सड़क परियोजनाओं से सुगम हुए यातायात और बढ़ी आर्थिक गतिविधियों की जानकारी का भी प्रचार-प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में सेवा-संकल्प अभियान की तैयारियों के संबंध में हुई बैठक में बताया गया कि अभियान के अंतर्गत 13 कार्यक्रम होंगे। इनमें आशीर्वाद का दीया, 25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत, नमो सेवा गाथा, आंगन का उत्सव, कहानी बदलाव की, विकसित भारत संकल्प यात्रा, सेवा ज्योति यात्रा, वडनगर से वाराणसी, सेवा मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान-सरकार आपके द्वार, रंगोली राष्ट्र, राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज और जनसेवक महाकुंभ पंचायत से पार्लियामेंट तक शामिल हैं। आशीर्वाद के दीया के अंतर्गत हर एक दीया, प्रधानमंत्री श्री मोदी के 25 वर्षों की जनसेवा के प्रति आभार तथा विकसित भारत 2047 के सामूहिक संकल्प का प्रतीक होगा। प्रत्येक परिवार दीप प्रज्वलित करके इस संकल्प का सहभागी बनेगा।

गर्मी, सूखे और अल नीनो ने बिगाड़ा अनाज का गणित, 2026 में वैश्विक उत्पादन 6.11 करोड़ टन गिरने का अनुमान

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने 2026 में वैश्विक अनाज उत्पादन का अनुमान घटाकर 298 करोड़ टन कर दिया है, जो 2025 के रिकॉर्ड उत्पादन से 6.11 करोड़ टन यानी 2 फीसदी कम है। हालांकि, यह फिर भी अब तक की दूसरी सबसे बड़ी पैदावार होगी। उत्पादन में सबसे बड़ी चोट मक्का पर पड़ने की आशंका है, जिसका वैश्विक उत्पादन 130.9 करोड़ टन रहने का अनुमान है।

यूरोप में गर्मी और सूखे ने फसल की संभावनाएं कमजोर की हैं। गेहूं का उत्पादन 81.07 करोड़ टन और चावल का 55.3 करोड़ टन रहने का अनुमान है। चावल उत्पादन में भी 1.9 फीसदी गिरावट की आशंका है, जिसमें अल नीनो और किसानों के घटते मुनाफे की बड़ी भूमिका है। चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि उत्पादन घटने के बावजूद 2026-27 में वैश्विक अनाज खपत 296.5 करोड़ टन तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं भंडार में महज 0.2 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद है। अगस्त में वैश्विक खाद्य कीमतें भी 1.9 फीसदी बढ़ी हैं। यानी फिलहाल दुनिया के पास पर्याप्त अनाज है, लेकिन गर्मी, सूखा, अल नीनो और अस्थिर व्यापार मार्गों का बढ़ता दबाव भविष्य की खाद्य सुरक्षा और आम लोगों की थाली के लिए गंभीर चेतावनी है। दुनिया की बढ़ती आबादी के लिए भोजन जुटाने की चुनौती एक बार फिर गहराती दिख रही है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने अपनी नई रिपोर्ट में 2026 के लिए जारी वैश्विक अनाज उत्पादन के अनुमान को घटाकर 298 करोड़ टन कर दिया है। यह 2025 की रिकॉर्ड पैदावार से 6.11 करोड़ टन यानी 2 फीसदी कम है। एफएओ के ताजा आकलन के मुताबिक, उत्पादन में सबसे बड़ी गिरावट मक्का में देखने को मिल सकती है। वैश्विक मक्का उत्पादन का अनुमान घटाकर 130.9 करोड़ टन किया गया है। यूरोप में लगातार गर्मी और सूखे ने फसल को नुकसान पहुंचाया है। खासकर फ्रांस और पोलैंड में उत्पादन की संभावनाएं कमजोर हुई हैं। भारत और पराग्वे के अनुमान में भी मामूली कमी की गई है। हालांकि अर्जेंटीना और ब्राजील में उम्मीद से बेहतर पैदावार इस गिरावट को कुछ हद तक थाम सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक गेहूं का वैश्विक उत्पादन 81.07 करोड़ टन रहने का अनुमान है। जुलाई के अनुमान से इसमें 42 लाख टन (0.5 फीसदी) की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन फिर भी यह 2025 के मुकाबले 3.8 फीसदी कम होगा। इसके बावजूद यह गेहूं की अब तक की दूसरी सबसे बड़ी पैदावार होगी। कनाडा और

मोरक्को में बेहतर उत्पादन की उम्मीद से वैश्विक अनुमान बढ़ा है, जबकि यूरोप और ब्रिटेन में कम बारिश और बढ़ते तापमान ने फसल पर असर डाला है। यह महज कोई आंकड़ा नहीं है, यह उन करोड़ों परिवारों का दर्द है जो पहले ही गरीबी, संघर्ष, और महंगाई की आग में जल रहे हैं और अब मौसम की इस मार से अपनी रोटी छिनने के कगार पर हैं। फोटो- सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) धान की कहानी भी राहत देने वाली नहीं है। 2026-27 में वैश्विक धान उत्पादन 55.3 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो पिछले सीजन के रिकॉर्ड स्तर से 1.9 फीसदी कम है। एफएओ के अनुसार, किसानों को मिलने वाला कम मुनाफा और अल नीनो से जुड़ी प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां उत्पादन में गिरावट की प्रमुख वजह हैं। यानी दुनिया की रसोई में रोजाना इस्तेमाल होने वाले इस सबसे अहम अनाज पर भी मौसम का दबाव साफ दिखाई दे रहा है। चिंता की एक और वजह यह है कि उत्पादन घटने के बावजूद अनाज की वैश्विक खपत बढ़ने का अनुमान है। 2026-27 में दुनिया में कुल 296.5 करोड़ टन अनाज की खपत की संभावना जताई गई है, जो पिछले साल से 55 लाख टन यानी 0.2 फीसदी अधिक है। रुझानों से पता चला है कि मक्का और अन्य मोटे अनाज तथा चावल की खपत बढ़ने की उम्मीद है। बढ़ती आबादी के कारण चावल की खपत लगातार बढ़ रही है। वहीं 2025 में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन के कारण पशु आहार और औद्योगिक इस्तेमाल में गेहूं की खपत बढ़ी थी, लेकिन 2026-27 में इसके कुछ कम होने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 2027 में सीजन खत्म होने तक दुनिया में अनाज का कुल भंडार 94.7 करोड़ टन रहने का अनुमान है। यह शुरुआती भंडार से सिर्फ 18 लाख टन यानी 0.2 फीसदी अधिक होगा। यानी उत्पादन और खपत के बीच अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वैश्विक खाद्य व्यवस्था के लिए बड़ी सुरक्षा-ढाल भी नहीं बन रही। एफएओ ने अपनी अन्य रिपोर्ट में अगस्त 2026 के दौरान वैश्विक खाद्य कीमतों में 1.9 फीसदी की बढ़ोतरी की भी पुष्टि की है। इससे आने वाले महीनों में खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर दबाव बढ़ने की आशंका है।

अब किसानों को सिंचाई के लिए दिन में भी उपलब्ध होगी बिजली -मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल = मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों को सतत रूप से सुविधाएं देने का कार्य किया जा रहा है। अब किसानों को सिंचाई के लिए दिन में भी बिजली की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे वे दिन के समय में भी अपनी फसलों में पानी दे सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कृषि उपज मंडी परिसर श्योपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव एवं किसान मेले को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने श्योपुर के किसानों से संवाद भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कृषि उपज मंडी श्योपुर में किसानों के लिए नवीन विश्राम गृह निर्माण के लिये 60 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। ग्वालियर एयरपोर्ट से कार्यक्रम में श्योपुर जिले के प्रभारी मंत्री एवं नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला, कृषि मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना, वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री रामनिवास रावत और अपेक्स बैंक अध्यक्ष श्री महेन्द्र सिंह यादव भी वर्चुअली उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है इसमें किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। किसानों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण की सुविधा दी जा रही है। खरीफ एवं रबी फसलों के लिए 6-6 माह की अवधि ऋण चुकाने के लिए निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब एक वर्ष कर दिया गया है, अर्थात किसान द्वारा जिस दिनांक से ऋण लिया जायेगा, उसे चुकाने की अवधि उस दिनांक से एक वर्ष तक की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अधिक से अधिक संख्या में दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जाये और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जाये। उन्होंने कहा कि श्योपुर जिले में

धान और गेहूं का बम्पर उत्पादन होता ही है। जिले के किसान मोटे अनाज का उत्पादन भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मंगलवार को ही मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपये की राशि प्रदाय की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपील की कि बच्चों को पढ़ाये तथा फिजूलखर्ची को रोकें, समाज में ऐसी परम्परा डालें, जिससे शादी-विवाह सहित अन्य सामाजिक आयोजनों में अधिक खर्च न हों। सामूहिक विवाह सम्मेलनों के माध्यम से विवाह संपन्न करायें। उन्होंने सभी को जन्माष्टमी की बधाई भी दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों से संवाद भी किया। इस दौरान ग्राम राडेप के किसान श्री मुकुट चौधरी ने बताया कि शासन की योजना में कृषि अभियांत्रिकी के माध्यम से उन्हें पराली प्रबंधन के लिये कृषि यंत्र सब्सिडी पर प्राप्त हुए हैं, पराली प्रबंधन के लिए सुपर सीडर खरीदा था, जिस पर 1 लाख 20 हजार रुपये का अनुदान भी प्राप्त हुआ। बलराम कृषि महोत्सव एवं किसान मेले में पशुपालन, कृषि, उद्यानिकी, मत्स्यपालन, एनआरएलएम द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बलराम कृषि महोत्सव एवं किसान मेले में आये किसानों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा खेती-किसानी की नवीन तकनीकी और फसलों के संबंध में लाभदायक जानकारी प्रदान की गई है। कार्यक्रम में श्योपुर में प्रगतिशील किसान श्री नरेन्द्र चौधरी, श्री भरत जाट, श्री शिशुपाल मीणा, श्री सोनू शर्मा, श्री बनवारी मीणा, श्री भुवनेश मीणा, श्री पूरण प्रजापति, श्री गोविंद पटेलिया और श्री मान सिंह पटेलिया को शॉल एवं प्रशस्ती पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

प्रदूषण में जारी उतार-चढ़ाव श्री गंगानगर सबसे प्रदूषित, आइजोल सबसे साफ; दिल्ली-फरीदाबाद में भी दिखा सुधार

नई दिल्ली। देशभर में वायु प्रदूषण का उतार-चढ़ाव जारी है। 6 सितंबर 2026 के सरकारी आंकड़ों में राजस्थान का श्री गंगानगर 186 एक्व्यूआई के साथ सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि मिजोरम की राजधानी आइजोल महज 19 एक्व्यूआई के साथ सबसे साफ शहर रहा।

श्री गंगानगर की हवा में पीएम10 का दबदबा रहा और प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा से करीब 300 फीसदी अधिक दर्ज किया गया। इसके मुकाबले आइजोल की हवा करीब 9.7 गुणा बेहतर रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 250 शहरों के आंकड़ों के अनुसार 92 शहरों में हवा साफ, 140 में संतोषजनक और 18 शहरों में मध्यम श्रेणी की रही। हालांकि साफ हवा वाले शहरों की हिस्सेदारी एक दिन में 7.1 फीसदी घटी है, जबकि मध्यम श्रेणी वाले शहरों की संख्या 5.9 फीसदी बढ़ी—जो प्रदूषण के दोबारा बढ़ने का संकेत है। गोरखपुर, बड़ी और तालचेर भी सबसे प्रदूषित शहरों में रहे। वहीं दिल्ली और फरीदाबाद में राहत दिखी। दिल्ली का एक्व्यूआई 59 से घटकर 55 और फरीदाबाद का 105 से 86 पर आ गया। आंकड़े बताते हैं कि देश की हवा भले फिलहाल ज्यादातर शहरों में संतोषजनक हो, लेकिन प्रदूषण की यह अस्थिर तस्वीर किसी बड़ी चिंता से कम नहीं है। सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि 06 सितम्बर 2026 को देश में श्री गंगानगर सबसे प्रदूषित रहा। इस दौरान वहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्व्यूआई) 186 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है। वहीं कल (05 सितम्बर) को सरकारी आंकड़ों में श्री गंगानगर का जिक्र नहीं था। रुझानों में यह भी सामने आया है कि श्री गंगानगर की हवा में प्रदूषण के महीन कण (पीएम10) पूरी तरह हावी है। देखा जाए तो वहां फिजाओं में घुला जहर इतना ज्यादा है कि वो लोगों को बेहद बीमार बना देने के लिए काफी है। श्री गंगानगर में स्थिति किस कदर खराब है, इसी बात से समझा जा सकता है कि वहां प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमासे 300 फीसदी अधिक है। दूसरी तरफ देश में आइजोल की हवा सबसे साफ है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक महज 19 रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में यदि देश के सबसे प्रदूषित शहर श्री गंगानगर की तुलना आइजोल से करें तो वहां स्थिति 9.7 गुणा खराब है। कल देश में कुड्डलोर की स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी, जब एक्व्यूआई 493 तक पहुंच गया था।

हालांकि आज सरकारी रुझानों में कुड्डलोर नदारद है। दिल्ली में कल से प्रदूषण में कमी आई है। दिल्ली में जहां कल एक्व्यूआई 59 दर्ज किया गया था, जो आज घटकर 55 पर पहुंच गया। मतलब की पिछले 24 घंटों में वहां वायु गुणवत्ता सूचकांक में 4 अंकों की गिरावट आई है। इसके साथ ही दिल्ली में आज भी वायु गुणवत्ता 'संतोषजनक' श्रेणी में बनी हुई है। 2026 के दौरान दिल्ली में साल का सबसे साफ दिन 09 जुलाई को दर्ज किया गया, जब एक्व्यूआई 48 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह 08 जुलाई 2026 को सूचकांक 59 और 07-06 सितम्बर को 63 रिकॉर्ड किया गया। वहीं 04 अगस्त और 22 जुलाई 2026 को सूचकांक 64 दर्ज हुआ। दूसरी तरफ 18 जनवरी 2026 को दिल्ली में साल का सबसे प्रदूषित दिन दर्ज किया गया, जब एक्व्यूआई बढ़कर 440 तक पहुंच गया था। दिल्ली की तरह ही फरीदाबाद में भी कल से प्रदूषण में कमी आई है। फरीदाबाद में जहां कल वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्व्यूआई) 105 दर्ज किया गया था, जो आज घटकर 86 पर पहुंच गया। इसके साथ ही 19 अंकों के सुधार के साथ फरीदाबाद में एक्व्यूआई मध्यम से संतोषजनक श्रेणी में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 06 सितम्बर 2026 को 250 शहरों के लिए जारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि इनमें से जहां करीब 36.8 फीसदी शहरों में हवा साफ है। वहीं 56 फीसदी में स्थिति संतोषजनक बनी हुई है, जबकि दूसरी तरफ 7.2 फीसदी शहरों में हालात चिंताजनक हैं। मतलब की देश के ज्यादातर शहरों में आज हवा संतोषजनक है। कल से देश में साफ हवा वाले शहरों की गिनती में 7.1 फीसदी की गिरावट आई है। दूसरी तरह संतोषजनक हवा वाले शहरों की गिनती में 5.3 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। रुझानों के मुताबिक मध्यम वायु गुणवत्ता वाले शहरों की गिनती में कल से करीब 5.9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जोकि चिंता का विषय है। आंकड़ों से पता चला है कि प्रदूषण के मामले में गोरखपुर (171) दूसरे जबकि बड़ी (163) तीसरे स्थान पर है। इसी तरह तालचेर (162) चौथे स्थान पर है। गुमिडीपूंडी (161) डू पानीपत (153) में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है, जो पांचवें और छठे पायदान पर हैं। वातवा (139) सातवें स्थान पर हैं। इसी तरह दस सबसे प्रदूषित शहरों में बिलाईपाड़ा (128), छल (123) और खैरथल (121) शामिल हैं। रुझानों में सामने आया है कि आज देश के दस सबसे प्रदूषित शहरों में ओडिशा के तीन शहर (तालचेर, बिलाईपाड़ा, छल) शामिल हैं।

उद्योगों की गर्मी का सौर समाधान-लागत घटेगी, प्रदूषण भी होगा कम

कई उद्योग उत्पादन प्रक्रिया के लिए आवश्यक उष्मा प्राप्त करने के लिए डीजल और गैस का इस्तेमाल करते हैं। आदर्श स्थिति तो यही है कि उत्पादन प्रक्रिया में उष्मा के लिए कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाए। इससे देश में वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर कम करने में मदद मिलेगी। सौर तापीय प्रणाली विकिरण (रेडिएशन) से मिलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल कर उष्मा देती है। यह एक व्यावहारिक और टिकाऊ विकल्प है।

इस तकनीक की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। आवश्यकता होने पर यह चौबीसों घंटे सौर ऊर्जा की आपूर्ति कर सकती है। जो उद्योग उष्मा की जरूरत पूरी करने के लिए सौर तापीय ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें दुग्ध, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, दवा और रसायन शामिल हैं। ये उद्योग अगर सौर तापीय ऊर्जा प्रणाली का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी परिचालन लागत काफी कम हो जाएगी क्योंकि डीजल एवं गैस की तुलना में इस प्रणाली में विकिरण का खतरा बिल्कुल नहीं है। हालांकि, भारत में डीजल एवं गैस से सौर तापीय प्रणाली की ओर बदलाव अभी शुरू होना बाकी है।

एक तरह से कहें तो इस प्रणाली की तरफ कदम बढ़ाने की शुरुआत अब तक नहीं होना 'बाजार की विफलता' का एक बड़ा मामला है। बाजार में ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं है जो सौर तापीय ऊर्जा प्रणाली बेचने या उपलब्ध कराने और इनकी मांग बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। यह प्रणाली हर औद्योगिक इकाई की उष्मा की खास जरूरतों के हिसाब से तैयार करनी पड़ती है और ये बड़े पैमाने पर मानकीकृत उत्पादन, विपणन और बिक्री के लिए उपयुक्त नहीं हैं। आपूर्ति नदारद रहने एवं किसी तरह का बढ़ावा नहीं मिलने के कारण इनकी मांग भी नहीं है। बाजार विफलता के ऐसे मामलों में बाजार में काम करने वाली ताकतों को सही दिशा देने के लिए सरकार को राह दिखानी पड़ती है। इसके लिए एक उपयुक्त रणनीति बनानी होगी। इसका केवल एक समाधान नहीं है।

हमारे पास सभी घरों में पारंपरिक तापदीप्त बल्बों की जगह ऊर्जा इस्तेमाल के

लिहाज से अधिक कारगर एलईडी बल्बों का इस्तेमाल करने और बिजली के बिल में बचत करने में मिली जबरदस्त सफलता का अनुभव है। बिजली मंत्रालय की ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने बार-बार बड़ी मात्रा में एलईडी बल्ब खरीदे जिससे उनकी कीमतें काफी कम हो गईं। इसने सभी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के साथ साझेदारी की। इन डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब दिए और लागत की वसूली किस्तों में की जिसे बिजली बिल में हुई बचत से आसानी से चुकाया जा सकता था। बिना किसी सब्सिडी के इस नए कार्यक्रम स्वरूप की वजह से यह बदलाव केवल पांच वर्षों में पूरा हो गया जो एक कीर्तिमान है।

सौर तापीय ऊर्जा में आगे बढ़ने का एक तरीका यह हो सकता है कि कोई सरकारी एजेंसी अलग-अलग उद्योगों में प्रायोगिक परियोजना लगाकर इन प्रणालियों की विश्वसनीयता और लागत में होने वाली बचत से सबको अवगत कराए। उदाहरण के लिए किसी खास औद्योगिक क्षेत्र में (जैसे टेक्सटाइल पार्क) में बन रही नई इकाइयों की पहचान की जा सकती है और उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से बनी नए सौर तापीय उष्मा प्रणाली से उष्मा लेने के लिए मनाया जा सकता है। यह काम गारंटी और देयता वाले अनुबंधों के जरिये उष्मा आपूर्ति करने का प्रस्ताव देकर किया जा सकता है। यह जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मानक दीर्घकालिक 'टेक ऑर पे' अनुबंध (खरीदार और विक्रेता के बीच कानूनी समझौता) के तहत आपूर्ति के लिए बोलियां मंगाई जा सकती हैं।

उष्मा की खरीद और आपूर्ति के लिए इन एक के बाद एक अनुबंधों के साथ एजेंसी पर केवल आकस्मिक देयता आएगी। ऐसा करने से सुनिश्चित आपूर्ति को लेकर औद्योगिक इकाइयों और पक्की खरीद व भुगतान को लेकर आपूर्तिकर्ताओं के मन में जो जोखिम का डर है वह दूर हो जाएगा। भविष्य में पार्क में उत्पादन और मांग बढ़ने के साथ-साथ इन सौर तापीय प्रणाली को मॉड्यूलर तरीके से लगाने के लिए जगह उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक पार्क विनिर्माताओं (डेवलपर) के साथ साझेदारी करने की जरूरत आएगी।